भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या : **364**

दिनांक 18 जुलाई , 2019 / 27 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उड़ान योजना का विस्तार

*** 364. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:**
डॉ. सुजय विखे पाटील:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत हवाई अड्डों के विस्तार और विकास हेतु छोटे नगरों को अभिज्ञात किए जाने का कार्य पूरा कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो इस योजना में शामिल हुए हैं तथा इसके अंतर्गत, विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित, विकसित किए जाने वाले नगरों और हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ अब तक अभिनिर्धारित एवं जारी की गई धनराशि कितनी है; और

(ग) इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'उड़ान योजना का विस्तार' विषय पर लोक सभा के दिनांक 18.07.2019 को पूछे जाने वाले मौखिक प्रश्न संख्या 364 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई सम्पर्कता को सुगम बनाने/बढ़ावा देने और हवाई यात्रा को आम जनता के लिए किफायती बनाने के उद्देश्य से दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) आरंभ की है। आरसीएस - उड़ान बाजार द्वारा चालित योजना है। इच्छुक एयरलाइनें कुछ खास मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर समय समय पर आरसीएस - उड़ान के तहत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर करती हैं।
गोवा, मिजोरम, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप को छोड़कर, 30 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने अपने अपने राज्यों में आरसीएस - उड़ान योजना के तहत उड़ानों के प्रचालनीकरण के लिए नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के असेवित/अल्पसेवित हवाईअड्डों/हवाई पट्टियों और सिविल एन्कलेवों का पुनरुत्थान करने का प्रस्ताव 06 मार्च, 2017 को अनुमोदित किया। तथापि, इन असेवित/अल्पसेवित हवाईअड्डों का पुनरुत्थान 'मांग द्वारा चालित' है, जो एयरलाइन प्रचालकों से ठोस प्रतिबद्धता के साथ- साथ राज्य सरकारों की ओर से विभिन्न रियायतें प्रदान किए जाने पर भी निर्भर करता है।

क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के पहले दौर में 27 नेटवर्क, दूसरे दौर में 90 नेटवर्क और तीसरे दौर में 95 नेटवर्क अवार्ड किए गए जिनमें 706 आरसीएस मार्ग शामिल हैं। 40 आरसीएस हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 186 आरसीएस मार्ग आरंभ किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र राज्य में कोल्हापुर, नांदेड़, ओजर (नाशिक), जलगांव और शोलापुर नामक पॉच (5) हवाईअड्डे हैं। कोल्हापुर, नांदेड़ और ओजर (नाशिक) में उड़ान प्रचालन पहले ही आरंभ हो चुके हैं। जलगांव हवाईअड्डा प्रचालनों के लिए तैयार है, किंतु आरसीएस उड़ान प्रचालन अभी आरंभ होने हैं। इस समय शोलापुर हवाईअड्डा तैयार नहीं है, क्योंकि उड़ान के रास्ते में बाधा (चिमनी) है। मध्य प्रदेश में एक हवाईअड्डा ग्वालियर है जहां आरसीएस उड़ान प्रचालन पहले ही आरंभ हो चुके हैं। आरसीएस - उड़ान के तहत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के हवाईअड्डों के संबंध में व्यय संबंधी ब्यौरा देने वाला वित्तीय विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

*****

अनुबंध

30.06.2019 तक व्यय को दर्शाने वाला वित्तीय विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	हवाई अड्डे का नाम	स्वीकृत राशि (करोड़)	30.06.19 तक व्यय
महाराष्ट्र			
1.	कोल्हापुर	235.76	45.72
2.	शोलापुर	19.40	11.50
3.	जलगांव	26.98	3.57
4.	नांदेड़	0.67	0.02
5.	ओज़र (नासिक)	17.67	0.00
मध्य प्रदेश			
1.	ग्वालियर	4.63	1.79